



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 703 राँची, बुधवार,

25 जुलाई, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-110/2017-922 (HRMS)-- श्री सागर कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1930, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा मनरेगा अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग एवं उच्च अधिकारियों के निदेशों की अवहेलना की गयी, जिसके कारण मनरेगा योजना का क्रियान्वयन बाधित हुआ एवं अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका तथा मनरेगा अन्तर्गत ससमय मजदूरों का भुगतान नहीं कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3(3) का उल्लंघन किया गया है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10019, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-13, दिनांक 1 जनवरी, 2018 द्वारा स्मारित किया गया, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा पत्रांक-06, दिनांक 15 जनवरी, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-861, दिनांक 1 फरवरी, 2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त मंतव्य के अनुसार, प्रपत्र- 'क' का गठन करने के समय मनरेगा योजना में उपलब्धि न्यून थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा बेहतर प्रयास कर संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की गयी। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री सागर कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण, हजारीबाग, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिका किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SAGAR KUMAR 20060400051	श्री सागर कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच) को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----